SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI : I do not like to enter into any controversy. (*Interruptions*).

SHRI CHITTA BASU : Just a minute.

MR. DPUTY-SPEAKER : He is replying to Mr. Rawat. (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER : Have you finished ?

SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURI : Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now, the next item.

Shri Bhishma Narain Singh.

14.51 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH) : With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 7th December, 1981, will consist of :—

(1) Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

(2) Consideration and passing of :—

(a) The Central Silk Board (Amendment) Bill, 1981.

(b) The Plantation Labour (Amendment) Bill, 1981, as passed by Rajya Sabha.

(c) The Chit Funds Bill, 1980, as reported by the Select Committee.

(d) The Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Amendment Bill, 1980, as passed by Rajya Sabha.

(3) Discussion and voting on :—

(a) Supplementary Demands for Grants (General) for 1981-82.

(b) Demands for Excess Grants (General) for 1979-80.

(4) Discussion on the Motion given notice of by Sarvashri N.K. Shejwalkar and Phool Chand Verma for annulment of All-India Services (Death-Cum-Retirement Benefits) Amendment Rules, 1981, at 5 p.m. on Wednesday, the 9th December, 1981.

(5) Further discussion on the International Situation on Thursday, the 10th December, 1981, after disposal of questions.

MR. DEPUTY-SPEAKER : There are about nine hon. Members who have given some subjects to be included in the Business. Shri Harikesh Bahadur.

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) : Two points I would like to suggest to be included in the agenda.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You simply read.

SHRI HARIKESH BAHADUR : First point is : The situation in the entire North-Eastern Region including Assam is very sensitive and serious. Government is a total failure.... (*Interruptions*).

MR. DEPUTY-SPEAKER : At 3 O'clock I will go to the next item. You just read.

SHRI HARIKESH BAHADUR : I am reading.

. . .

Government is a total failure in solving the problem of foreign nationals in Assam. Extremists are very active in the other parts of that region. Keeping in view the seriousness of the crisis the matter requires immediate attention of Parliament. Therefore, this matter should be discussed in the House during the next week. Second point : The people in Rajasthan are suffering due to drought. This is a matter of serious concern. Therefore, a discussion should be allowed on this subject in the House during next week.

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani) : The Aligarh Muslim University (Amendment) Bill which was introduced long ago, should be taken up for discussion without further delay.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Jai Pal Singh Kashyap

श्री जयपाल सिंह कश्यप (ग्रावंला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित विषय ग्रागामी सप्ताह की सूची में विचार के लिए शामिल करना चाहता हूं :

(1) बरेली बदायूं जिले के मध्य स्थित चापट नामक स्थान पर रसायनिक खाद का कारखाना स्थापित करने ग्रौर ग्रावंला लोक सभा क्षेत्र में सूती कताई कारखाना, डिग्री कालेज, मैडिकल कालेज व इंजीनियरिंग कालेज ग्रौर प्रत्येक ब्लाक में एक कारखाना खुलना चाहिए, जिसको ग्रागामी सप्ताह के कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए।

(2) बरेली–कासगंज रेल मार्ग पर चलने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए ग्रौर गोहाटी एक्सप्रेस करके मथुरा तक ले जाना चाहिए ताकि उत्तरी भारत का सम्बन्ध मध्य भारत व दक्षिण से हो सके ग्रौर समस्त बन्द ट्रेनें तुरन्त चलाई जायें व समय का विशेष ध्यान रखा जाए व बरेली से दिल्ली को नई एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की जनता द्वारा काफी दिनों से मांग चल रही है। इस पर भी ग्रागामी सप्ताह में चर्चा ग्रावश्यक है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Mani Ram Bagri. Before I call Mr. Mani Ram Bagri, I want to make one thing clear. According to the decision taken at the meeting of the Speaker with the Leaders, the Members of the Business Advisory Committee do not make any submissions in the House after the statement of the Minister of Parliamentary Affairs regarding business for the following week. Shri Mani Ram Bagri, who has been nominated on the Business Advisory Committee on 1 December, 1981, has requested permission to make a submission regarding business for the next week. I am allowing Shri Bagri to make the submission as a special case as he has been nominated on the Committee only a few days back and has so far not attended the sitting of the Committee.

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रगले हफ्ते की कार्यवाही की सूची में नीचे लिखे प्रश्नों को जोड़ा जाए, क्योंकि निम्नांकित प्रश्न बहुत ही ग्रावश्यक एवं महत्वपूर्ण हैं :—

1. किसानों की जो जमीन सरकारी या सरकारी विधान द्वारा ग्रधिग्रहित की जा रही है ग्रौर उसके दाम उन्हें "ना" के बराबर दिए जा रहे हैं। जब कि वही जमीन ग्रागे चल कर सैकड़ों ग्रौर हजारों

[श्री मनीराम बागड़ी]

रुपये की दर पर बेची जा रही है । सरकार के सहयोग से गरीब किसानों का जो शोषण हो रहा है इस पर अविलम्ब चर्चा की जाए और रोकने का उपाय किया जाए ।

2. देश भर की जेलों में जो जुल्म जैसे—कानपुर जेल में बच्चों के साथ (लड़कों के साथ) बलात्कार, बिहार में तीस वर्ष से किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बन्द रखना तथा दिल्ली की जेलों में किए जा रहे अत्याचार एवं बलात्कार और बदचलनी के बारे में सोच विचार के लिए इस विषय को जरूर रखा जाना चाहिए ।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 4-12-81 के पुनरीक्षित कार्य सूची के मद सं० 8 में निम्नलिखित विषयों को आगामी सप्ताह में विचारार्थ रखने का निवेदन करता हूं :—

(1) लम्बे अरसे से सरकार द्वारा राष्ट्रीय वेतन नीति निर्धारण का आश्वासन दिया जा रहा है । पर इसके कार्यान्वयन में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है । फलस्वरूप देश के विभिन्न भागों में उद्योगपतियों द्वारा मजदूरों खासकर असंगठित मजदूरों का भीषण शोषण हो रहा है। उदाहरणार्थ देश में लगभग 50 लाख बीड़ी मजदूर हैं। कई राज्यों में इनकी मजदूरी काफी कम है । जहां इस वर्ष न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण भी हुआ है वहां उसे लागू नहीं कराया जा रहा है । जैसे बिहार में । यहां उल्टे मजदूरों द्वारा कानूनी मजदूरी लागू करने की मांग करने पर उन्हें और उनके नेताओं को सरकारी अधिकारियों और पुलिस द्वारा पीटा जा रहा है और उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है । अतः राष्ट्रीय वेतन निर्धारण की नीति का कार्यान्वयन और इसे लागू करने के लिए सक्षम एजेंसी का गठन आवश्यक है, जिसको अगले सप्ताह की कार्यसूची में रखा जाए।

(2) देश के कृषि योग्य भूमि का बड़ा भाग असिंचित है । राज्य सरकारें सिंचाई की बड़ी योजनाओं को लेने में आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं हैं । इसका असर देश की आर्थिक स्थिति पर काफी गहरा पड़ रहा है । बिहार में ठाठर-तिलैया जलाशय योजना और गंगा नदी से नहर निकालकर नालन्दा, नवादा, मुंगेर, वारिस अलीगंज, गया आदि दक्षिण की ओर सिंचाई की व्यवस्था तथा मोकामा टाल योजना आदि के द्वारा हजारों-हजार एकड़ जमीन की सिंचाई की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार द्वारा ही संभव है । अतः इसे विचारार्थ अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ा जाए ।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur) : There are two issues. One is the role and functioning of the nationalised banks. We find that the whole purpose of nationalisation is being frustrated. On the other hand, the banks are really standing in the way of revival of sick industries by their attitude which is stifling industrial growth. I want that issue to be discussed next week.

The second issue is the serious situation arising out of the non-filling of vacancies in the High Courts, which is aggravating the mounting arrears in this country. The whole system is on the verge of collapse. This should also be discussed.

Sir, you asked us to summarise but the Minister is not listening,

MR. DEPUTY SPEAKER: He is very much listening.

15 hrs.

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर): बिहार के संथाल परगना जिले के अन्तर्गत

ईस्टर्न कोल फील्ड के चित्रा कोलियरी के निकट स्थित सहजोरी में बेरोजगार हरिजन और आदिवासियों ने कोयला खान विकसित किया था। राष्ट्रहित में यह उचित होगा कि उस खान का तत्काल अधिग्रहण कर वहां काम करने वाले मजदूरों का नियोजन उस खान में कर लिया जाए। उल्टे सरकार ने कई सौ मजदूरों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। उन्हें जेल से निकाल कर वहां नियोजित कर दिया जाना चाहिए।

वर्तमान उद्देश्यविहीन शिक्षा पद्धति में सुधार और शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि को रोकने के लिए विश्वविद्यालय की उपाधि को सरकारी सेवा पूर्ति से असम्बद्ध कर दिया जाना चाहिए। सरकारी सेवा, बैंक सेवा, और अन्य सेवाओं में दस जमा दो पास किए नवयुवकों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से हो।

मैं चाहता हूं कि इन दो विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए।

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): I suggest that the following two items be included in the Government business for the next week.

One is about the demolition of Gandhiji's Prison Cell. It is reported that the tiny South African Prison Cell in which Mahatma Gandhi formulated his 'satyagraha' philosophy is going to be demolished by the authorities under the pretext that it had 'nuisance' value.

The Government must make immediate efforts to prevent the demolition of this prison cell from which emanated Gandhiji's universal message of satyagraha. I request the Government to make a statement in this regard.

The second item is about acquisition of lands of kisans of Badli and other villages. The kisans from Badli and other villages in the vicinity of Delhi who staged a peaceful demonstration outside the Parliament on 30 November, 1981 demanded that the acquisition of the fertile lands of the kisans from these villages at a low compensation of Rs. 1.25 to Rs. 2.40 per sq. yard should be stopped forthwith and no acquisition of land should be resorted to unless the existing Land Acquisition Act, 1894 was amended so as to protect the interest of the kisans.

On 19 March, 1981 the Government had already given as assurance in Lok Sabha to protect the interest of these villagers whose lands were being acquired with low compensation.

I request the Government to make a statement on the subject reiterating its earlier assurance to these kisans.

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: I am extremely thankful to the hon. Members for the valuable suggestions that they have made. I will go through the records. If I feel something necessary, which is to be brought to the notice of the BAC, will do so.

CRIMINAL LAW (AMENDMENT) BILL

RECOMMENDATION TO RAJYA SABHA TO APPOINT A MEMBER OF RAJYA SABHA TO JOINT COMMITTEE

SHRI D. K. NAIKAR (Dharwad North): I beg to move:

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do appoint a Member of Rajya Sabha to the Joint Committee on the Bill